बिहार विधान परिषद्

सत्र-198

26 जुलाई, 2021

प्रारंभिक संबोधन

श्री अवधेश नारायण सिंह

कार्यकारी सभापति

प्रारंभिक संबोधन
सत्र-198
26 जुलाई, 2021

माननीय नेता, सत्तारूढ़ दल
मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यगण
विभिन्न दलों के माननीय नेतागण
बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण

बिहार विधान परिषद् का 198वां सत्र आज से आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बिहार विधान परिषद् के विभिन्न दलों के माननीय नेतागण तथा माननीय सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही, लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ एवं सजग प्रहरी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार-छायाकार प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं।

बिहार विधान परिषद् के इस मानसून सत्र में आज दिनांक 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक कुल पांच बैठकें होंगी। मुझे आशा है कि इस छोटे सत्र में जनता के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों एवं प्रदेश के विकास से जुड़े ज्यादा-से-ज्यादा विषयों को सदन पटल पर लाया जाएगा।

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में राज्य सरकार ने अपने सभी संभव संसाधनों को झोंक दिया था। माननीय मुख्यमंत्री बार-बार दोहराते रहे हैं कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित लोगों का होता है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस महामारी के कारण हुई मृत्यु से प्रभावित परिवारजनों को चार लाख रुपया सहायता अनुदान दिया जाएगा। कोरोना, अतिवृष्टि एवं वज्रपात से प्रभावित परिवारों के कल्याण संबंधी योजनाओं को सरकार द्वारा प्राथमिकता दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि आपदाओं से पीड़ित जनता के दुखों को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है।

कोरोना टीकाकरण को लेकर केन्द्र सरकार की सदाशयता एवं राज्य सरकार की सजगता के कारण बिहार अग्रणी राज्य बना है। कोरोना के तीसरे दौर के संकट की आशंका के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था हेतु 'बाल हृदय योजना' सरकार की संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

इस बरसात में वज्रपात की चपेट में आकर कई लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इस समस्या से निबटने के लिए जरूरी एहतियात बरतने के साथ अन्य जरूरी उपायों पर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है।

राज्य के युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 200 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य स्वागत योग्य है। राज्य के निराश्रित, उपेक्षित, बेसहारा एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न शहरों में वृद्धजन आश्रय स्थल गृह का संचालन करने की योजना का व्यापक स्वागत हुआ है।

कोरोना महामारी के कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए समय पर निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हो पाई। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा नहीं आए, इसके लिए सरकार ने पूर्व से निर्वाचित जन

प्रतिनिधियों को परामर्शी समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करने का निर्णय लिया। सरकार के इस अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय से लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हुई है।

माननीय सदस्यों के संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए विधान परिषद् के नवनिर्मित भवन के भूतल पर 'सुविधा केन्द्र' की स्थापना की गई है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस केन्द्र का अधिक से अधिक उपयोग करें।

पिछले सत्रों की तरह इस सत्र में भी माननीय सदस्यगण, परिषद् सचिवालय के पदाधिकारी-कर्मचारीगण एवं मीडिया प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग की आशा रखता हूं।

अंत में, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं।

धन्यवाद !

अवधेश नारायण सिंह
26 जुलाई, 2021